Work Executed Under Amrut Scheme

97. **Dr. Krishan Lal Middha, M.L.A.:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the work of storm water and sewerage line is being executed under the Amrut Scheme in Jind City; if so, the details of the tender allotted for abovesaid work; and

(b) whether the abovesaid work has not been completed in the stipulated period; if so, the action taken by the Government against officers/officials and contractor responsible for delay in completing the abovesaid work ?

ANIL VIJ, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir.

a) Yes, it is a fact that the work of storm water and sewerage line is being executed under the AMRUT Scheme in Jind City. The details of tenders allotted for above said works are as follows:

Name of Work	Original Agreement Amount (Rs. in Crores)	Date of Allotment	Enhanced Agreement Amount (Rs. in Crores)	Date of Completion as per Work Order	Extended Date of Completion
Storm Water Drainage	19.97	28.05.2018	24.62	07.12.2019	31.12.2020
Sewerage	6.77	06.11.2018	11.70	15.08.2019	31.12.2020

b) Yes, the above said work has not been completed in the stipulated period.

During the execution of work, some No Objection Certificate (NOC) is required from other departments like NHAI, PWD (B&R), Railways etc. and Municipal Council, Jind has applied

for the same. But, required NOCs were not received on time even by making various efforts which resulted into delay in work.

In the large interest of public, a number of colonies regularized recently have been included for the laying of sewerage line. On the request of Public Health Engineering Department - Jind, some old sewer lines are replaced and the alignment of some of sewer lines has to be changed which resulted into delay in work. Nationwide Lockdown is also a reason for delay in work.

By considering the above factors and on the recommendation of Municipal Council-Jind, the State Level Technical Committee under AMRUT has extended the time period of the above two works.

Both the works are in progress and likely to be completed by 31.12.2020.

अमृत योजना के अंतर्गत निश्पादित कार्य

97. डॉ० कृश्ण लाल मिढ़ा, एम०एल०ए० : क्या भाहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या यह तथ्य है कि जींद भाहर में अमृत योजना के अंतर्गत बरसात के पानी तथा सीवरेज लाईन का कार्य किया जा रहा है; यदि हां, तो उपरोक्त कार्य के लिए आवंटित किए गए टेंडर का ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया है; यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त कार्य को देरी से पूरा करने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों तथा ठेकेदार के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

अनिल विज, भाहरी स्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान जी ।

(क) हां, यह तथ्य है कि जींद भाहर में बरसाती पानी और सीवरेज लाइन के कार्य अमृत योजना के तहत निश्पादित किए जा रहे

हैं। उपरोक्त कार्यों के लिए आबंटित निविदाओं का विवरण निम्नानुसार है:

कार्य का नाम	मूल अनुबंध रा□ा (रूपये करोड़ों में)	आबंटन की तिथि	वर्धित अनुबंध रा□ा (रूपये करोड़ों में)	कार्य आदे□ा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की बढ़ाई गई तिथि
बरसाती पानी की निकासी	19.97	28.05.2018	24.62	07.12.2019	31.12.2020
सीवरेज	6.77	06.11.2018	11.70	15.08.2019	31.12.2020

(ख) हां, उपरोक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं हुआ है।

कार्य के निश्पादन के दौरान, अन्य विभागों जैसे कि एनएचएआई, पीडब्लूडी (बी एण्ड आर), रेलवे इत्यादि से कुछ अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जाने की आव□यकता है और नगर परिशद, जीन्द द्वारा इनके लिए आवेदन कर दिया गया है। परन्तु विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए थे जिसके फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने में देरी हुई।

जनहित में, सीवरेज लाइन बिछाने के लिए हाल ही में नियमित की गई कॉलोनियों को भाामिल किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुरोध पर कुछ पुरानी सीवर लाइन को बदला गया है तथा कुछ सीवर लाइन के संरेखण को बदलना पड़ा जिसके फलस्वरूप कार्य में देरी हुई। राश्ट्रव्यापी लॉकडाउन भी कार्य में देरी का एक कारण है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए तथा नगर परिशद, जीन्द की अनु□ांसा पर, अमृत के तहत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त दोनों कार्यों की समयावधि बढ़ा दी गई है।

दोनों कार्य प्रगति पर हैं और 31.12.2020 तक पूर्ण होने की संभावना है।